कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 9 | मई 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

मई दिवस ज़िंदाबाद!

मज़दूरों-किसानों के शोषण को ख़त्म करने के संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, मई दिवस, 2022

मज़दूर साथियों,

आज मई दिवस है, सभी देशों के मज़दूरों के लिए जश्न मनाने का दिवस है। हमारे देश के कोने-कोने में मज़दूर जुझारू रैलियों, मीटिंगों और जुलूसों में हिस्सा ले रहे हैं। हम अब तक हासिल की हुई जीतों पर खुशियां मना रहे हैं और अपनी असफलताओं से सबक लेकर, उन पर चर्चा कर रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी सभी देशों के मज़दूरों को सलाम करती है, जो पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़, राष्ट्रीय दमन, नस्लवाद, फासीवाद और साम्राज्यवादी जंग के ख़िलाफ़, अपने अधिकारों के लिए तथा क्रांति और समाजवाद की फतह के लिए, बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

हम फिर से प्रण लें कि हम मज़दूर बतौर और मानव बतौर, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को बिना कोई समझौता किए, निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आइए, हम वादा करें कि हम सभी प्रकार के शोषण से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए संघर्ष करेंगे, एक ऐसा समाज जिसमें मेहनत करने वालों को अपने सामूहिक श्रम का फल मिलेगा और जहां कोई भी दूसरों के श्रम के शोषण करके अपनी खुद की दौलत को नहीं बढ़ा पाएगा।

बीते वर्ष के दौरान हमने अपने अधिकारों के लिए बड़े ज़ोरदार एकजुट संघर्ष किए हैं। 20 करोड़ से अधिक मज़दूरों ने 28 और 29 मार्च को हुई, दो दिवसीय सर्व हिन्द आम हड़ताल में भाग लिया था। कोयले की खदानों, इस्पात के कारखानों, पैट्रोलियम रिफायनरी, बिजली वितरण कंपनियों, रेलवे और सड़क परिवहन, बैंकिंग और बीमा, रक्षा क्षेत्र, आदि के मज़दूर, विनिर्माण मज़दूर और सेवा क्षेत्र के मज़दूर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, कृषि क्षेत्र में खेत मज़दूर, आंगनवाड़ी और आशा कर्मी – सभी ने मिलकर बड़ी कठिन हालतों में बहुत सारे बहादुर संघर्ष किए हैं।

हम मज़दूरों ने बड़ी सक्रियता के साथ किसानों के संघर्ष का समर्थन किया। किसान आंदोलन ने मज़दूरों की यूनियनों के मांगपत्र का समर्थन किया है। मज़दूरों और किसानों की एकता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।

हम फिर से प्रण लें कि हम मज़दूर बतौर और मानव बतौर, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को बिना कोई समझौता किए, निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आइए, हम वादा करें कि हम सभी प्रकार के शोषण से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए संघर्ष करेंगे ...

हम चार लेबर कोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो पूंजीपति वर्ग के हित के लिए मज़दूरों के अधिकारों को पांव तले कुचल देते हैं। हम जीने लायक वेतन के लिए, 8 घंटे काम के दिन के लिए और ठेका मज़दूरी को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हम उदारीकरण और निजीकरण के सरमायदारों के मज़दूर-विरोधी, समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्यक्रम को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरमायदारों ने बड़े घमंड के साथ ऐलान कर दिया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों को हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों – बैंकिंग, बीमा, बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम और रक्षा उत्पादन – सभी क्षेत्रों में मज़दूर पूरी ताक़त के साथ सड़कों पर उतरकर, समाज के इन अनमोल संसाधनों को निजी इजारेदार कंपनियों के हाथों बेच देने के इन प्रयासों का विरोध कर रहे हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, बिजली, पानी, शौच प्रबंधन, रेल और सड़क

शेष पृष्ठ 2 पर

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा :

लोगों को बांटने और अपनी हुकूमत को मजबूत करने का हुक्मरान वर्ग का पसंदीदा तरीक़ा

उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को लोगों के ख़िलाफ़ जो हिंसा फैलाई गई थी और इसके साथ-साथ, हाल के हफ्तों में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक में भी जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई है, उसे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के आपसी झगड़ों के रूप में दर्शाया गया है। यह सोच-समझकर फैलाया गया बहुत बड़ा झूठ है। इन सभी जगहों पर, लोगों ने साफ़-साफ़ बताया है कि हिंसा को फैलाने वाले हथियारबंद गुंडे उनके इलाके से नहीं थे। वे कहीं बाहर से लाए गए थे।

इनमें से किसी भी जगह पर, अलग-अलग धर्म के लोगों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया, एक दूसरे का क़त्ल नहीं किया। इसके विपरीत, लोग भड़काऊ गुंडों का विरोध करने के लिए और एक दूसरे को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इन सभी जगहों पर लोग बीते कई दशकों से शांति और अमन-चैन के साथ मिलकर रहते आये हैं और आपस में सुख-दुख बांटते रहे हैं।

राज्य तंत्र तथा समाचार माध्यम और सोशल मीडिया पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके, हुक्मरान सरमायदार वर्ग बहुत बड़ा झूठ फैला रहा है। यह झूठी ख़बर फैलाई जा रही है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है।

दिल्ली और कई अन्य जगहों पर अधिकारियों ने पहले तो मेहनतकश लोगों को इस हिंसा के लिए दोषी ठहराया और उसके बाद उनकी दुकानों और घरों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र भेज दिए। हुक्मरान वर्ग यह प्रचार कर रहा है कि वह "अवैध" झुग्गियों को इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि ये झुग्गी-बस्तियां तरह-तरह के अपराधों के तथाकथित स्रोत हैं।

हिन्दोस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, यह अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में संघर्ष नहीं है। यह शोषकों और शोषितों के बीच में संघर्ष है। जनसमुदाय को शोषण और दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष के रास्ते से भटकाने के लिए, हुक्मरान सरमायदार धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाते हैं ...

हक़ीक़त तो यह है कि हुक्मरान पूंजीपति वर्ग और उनके राजनीतिक प्रतिनिधि ही इन झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों को बसाते हैं, जहां मज़दूरों को अमानवीय हालतों में जीने को मजबूर किया जाता है। हुक्मरान सरमायदार वर्ग और उसके राजनीतिक नेता झुग्गी-झोपड़ियों की स्थापना इसलिए करते हैं ताकि पूंजीपतियों को सस्ते श्रम का अनवरत स्रोत उपलब्ध हो तथा राजनीतिक पार्टियों को बाहुबल का स्रोत उपलब्ध हो। इन बस्तियों के निवासी हुक्मरान वर्ग व उसकी राज्य की मशीनरी और उसकी राजनीतिक पार्टियों के दबाव के तले जीने को मजबूर होते हैं। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में ऐसी झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों और पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले अधिकतम मज़दूर सत्ता पर बैठी हुई ताक़तों के दमन का निरंतर शिकार बनकर जीते हैं। जब-जब पूंजीपति वर्ग चाहता है, तब-तब राज्य की मशीनरी इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों और संपत्तियों को उजाड़ देती है और उनकी ज़मीन को बड़े-बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथों सौंप देती है। फिर यह झूठा प्रचार फैलाया जाता है कि किसी ख़ास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सभी मज़दूर एकजुट होकर उन मेहनतकशों की हिफ़ाज़त में आगे न आयें, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं।

हिन्दोस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, यह अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में संघर्ष नहीं है। यह शोषकों और शोषितों के बीच में संघर्ष है। जनसमुदाय को शोषण और दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष के रास्ते से भटकाने के लिए, हुक्मरान सरमायदार धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाने और लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश करते रहते हैं।

शेष पृष्ठ 2 पर

मई दिवस के अवसर पर पार्टी का बयान

पृष्ठ 1 का शेष

परिवहन, बैंकिंग और बीमा – ये सभी आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। हम अधिकार बतौर इन सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी सेवाओं और समाज की दूसरी ज़रूरतों को पूंजीपतियों के मुनाफ़े का स्रोत बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं।

हिन्दोस्तान को सभी कृषि उत्पादों की खरीदी के लिए एक सर्वव्यापक सार्वजनिक ख़रीदी व्यवस्था की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए किसानों को अपनी उपज के लिए लाभदायक दाम सुनिश्चित हो सके। हिन्दोस्तान को एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की सख़्त ज़रूरत है, जिसमें सभी मेहनतकश लोगों को सस्ते दामों पर पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो सकें। ये शहरों और गांवों के सभी मेहनतकश लोगों के लिए, आधुनिक मानव जीवन को सुनिश्चित करने की ज़रूरी शर्तें हैं। ये मज़दूरों और किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगें हैं।

मेहनतकश बहुसंख्या की इन लंबित मांगों को पूरा करना अवश्य मुमकिन है। लेकिन ये मांगें इसलिए पूरी नहीं की जाती हैं क्योंकि अधिकतम मुनाफ़ा हड़पने की इजारेदार पूंजीपतियों की लालच इन्हें पूरा होने से रोक देती है। इजारेदार पूंजीपति मज़दूरों के शोषण और किसानों की लूट को खूब तेज़ करके जल्दी से जल्दी हर क्षेत्र में खुद को और अमीर बनाना चाहते हैं। सरमायदारों की हुकूमत समाज की प्रगति के लिए एक रुकावट बन गयी है।

हमारे लोगों की सभी समस्याओं का स्रोत पूंजीवाद की आर्थिक व्यवस्था और मज़दूरों व किसानों पर सरमायदारों की हुकूमत की हिफ़ाज़त करने वाला राज्य है। हिन्दोस्तानी गणराज्य और उसके सभी संस्थान – सरकार चलाने वाली पार्टी और मंत्रीमंडल, और उसके साथ–साथ, संसदीय विपक्ष, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, न्यूज़ मीडिया – ये सब मज़दूरों और किसानों पर सरमायादारों की हुकूमशाही को क़ायम करने के साधन हैं।

बहु पार्टीवादी, प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकश लोगों को हमेशा ही सत्ता से बाहर रखा जाये। फ़ैसले लेने की ताक़त मंत्रीमंडल के हाथों में संकेंद्रित है और इस मंत्रीमंडल को संसद में बहुमत–प्राप्त पार्टी द्वारा गठित किया जाता है। सरमायदार यह फ़ैसला करते हैं कि उनकी भरोसेमंद पार्टियों में से किस पार्टी को किसी खास समय पर, सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। सरमायदार चुनावों के ज़रिए अपनी हुकूमत को वैधता देते हैं।

मज़दूर साथियों,

बीते साल में, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के दौरान अपनी एकता को काफी मजबूत किया है। हम मज़दूर अपनी पार्टी और ट्रेड यूनियन के संबंधों को एक तरफ करके, संघर्ष के एक सांझे झंडे तले एकजुट हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों के मज़दूर एकजुट होकर, निजीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ संघर्ष करने के लिए आगे आ रहे हैं। मेहनतकश लोग ज्यादा से ज्यादा हद तक यह समझ रहे हैं कि "एक पर हमला सब पर हमला है"।

सरमायदारों को मज़दूरों और किसानों की इस बढ़ती एकता से बहुत डर है। सरमायदारों ने हमारी एकता को तोड़ने की अपनी कोशिशों को और तेज़ कर दिया है। वे इसके लिए तरह–तरह के पैशाचिक तौर–तरीक़े अपना रहे हैं। देश के कई इलाकों में राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है धर्म के आधार पर हमें बांटना।

देश के कई इलाकों में जो हिंसा फैलाई जा रही है, जैसे कि उत्तर–पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, उसे अलग–अलग धार्मिक समुदायों के बीच टकराव के रूप में दर्शाया जा रहा है। यह सरासर झूठ है। राज्य के समर्थन के साथ हथियारबंद गुंडे इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर हिंसक हमले कर रहे हैं।

कई दशकों से अमन–शांति के साथ, आपस में मिलकर और दुख–दर्द बांटकर साथ जीते हुए लोग, इन हालातों में एक दूसरे की हिफ़ाज़त करने के लिए बाहर निकल कर आए हैं।

राजकीय आतंकवाद और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा हुक्मरान वर्ग का पसंदीदा हथकंडा है, जिसका वह बार–बार इस्तेमाल करता है। हुक्मरान वर्ग मज़दूरों और किसानों की रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर हो रहे सब–तरफा हमलों के ख़िलाफ एकजुट संघर्ष में हमारी एकता को तोड़ने के लिए बार–बार इसका इस्तेमाल करता है।

दिल्ली और देश के कई इलाकों में अधिकारियों ने फिर से झुग्गी–बस्तियों और मेहनतकशों की बस्तियों को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। उन स्थानों पर रहने वाले मेहनतकशों पर 'अपराधी और राष्ट्र–विरोधी' होने का आरोप लगाया जा रहा है।

हक़ीक़त तो यह है कि झुग्गी–बस्तियों से ही पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों के लिए सस्ते श्रम की बेरोक सप्लाई सुनिश्चित होती है। ये बस्तियां कई दशकों से बसी हुई हैं। यहां के निवासियों के पास वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का कनेक्शन, आदि सब कुछ है। बड़े पूंजीपति राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर इन मज़दूरों ने अपना आशियाना बनाया है, ताकि पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाने की अपनी लालच को पूरा कर सकें। सरमायदार और उनकी मीडिया बड़े सोचे–समझे तरीके से, लोगों के घरों की तोड़फोड़ को सांप्रदायिक रंगों में पेश कर रहे हैं, ताकि हम मज़दूर अपने भाइयों और बहनों पर हो रहे हमले का एकजुट होकर विरोध न करें।

मज़दूर साथियों,

हमारे देश में अलग–अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष मुट्ठीभर शोषकों और शोषित बहुसंख्या के बीच में है। यह इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में सरमायदारों तथा दूसरी तरफ, मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों के बीच में संघर्ष है।

सरमायदार देश को हमारे हितों के ख़िलाफ़, एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। वे देश के अनमोल संसाधनों और प्राकृतिक संपत्ति को देशी–विदेशी पूंजीपतियों के हाथों बेच रहे हैं। हमारे सरमायदार मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन और शांति के लिए सबसे बड़े ख़तरे, अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। वे हमारे लोगों तथा पड़ोसी देशों के लोगों के बीच में दुश्मनी को उकसाते रहते हैं। वे देश के मज़दूरों और किसानों को अपने असली दुश्मनों, यानि हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग और अमरीकी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ लड़ने के रास्ते से हटाना चाहते हैं। वे हमारे देश के मज़दूरों और किसानों को दूसरे देशों के मज़दूरों और किसानों के ख़िलाफ़ लड़ाना चाहते हैं।

हमें अपनी एकता को तोड़ने और अपने संघर्ष को ख़त्म करने के सरमायदारों के प्रयासों से सतर्क रहना होगा। हमें अपनी जुझारू एकता, सभी मज़दूरों की एकता तथा मज़दूरों और किसानों की एकता को बनाना तथा और मजबूत करना होगा। हमें खुद को एक ऐसी राजनीतिक ताक़त बनाना होगा, जो देश की बागडोर को संभालने का दायित्व उठाने के क़ाबिल हो और सरमायदारों तथा उनकी पार्टियों को उस स्थान से हटाने में क़ामयाब हो।

हम मज़दूर और किसान समाज की बहुसंख्या हैं। हम हिन्दोस्तान की दौलत को पैदा करते हैं। हमें हिन्दोस्तान के मालिक बनना होगा। ऐसा करके ही हम पूरी अर्थव्यवस्था को सभी को सुख और सुरक्षा दिलाने की नई दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसा करके ही हम हिन्दोस्तान को दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया में शांति का कारक बना सकेंगे।

मज़दूर साथियों,

आज से 132 वर्ष पहले, 1 मई, 1890 को यूरोप के सभी देशों के मज़दूरों ने 8 घंटे के काम के दिन की मांग को लेकर, रैलियां और हड़तालें आयोजित करके, संयुक्त रूप से मई दिवस का जश्न मनाया था। 1889 में स्थापित सोशलिस्ट इंटरनेशनल के आह्वान पर, मज़दूरों ने ऐसा किया था। उस समय से लेकर आज तक सारी दुनिया में मई दिवस का आंदोलन फैल गया है। सभी देशों के मज़दूर अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और पूंजीवादी शोषण से मुक्त, साम्राज्यवादी वर्चस्व तथा गुलामी और साम्राज्यवादी जंग से मुक्त दुनिया की स्थापना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आइए, हम सभी मज़दूरों के अधिकारों के लिए, ज़मीन को जोतकर पूरे समाज का पेट भरने वालों के अधिकारों के लिए, अपने एकजुट संघर्ष को और तेज़ कर दें। आइए, हम इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में हमारे शोषकों के ख़िलाफ़, अपनी जुझारू एकता को और मजबूत करें।

आइए, हमें बांटने के हुक्मरान वर्ग के सभी प्रयासों को नाक़ामयाब करें। आइए, सरमायदारों की हकूमत की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, देश के सभी शोषित और पीड़ित लोगों को लामबंध करें।

हमारा उद्देश्य जायज़ है। हम बहुसंख्यक लोगों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जीत अवश्य होगी।

मज़दूर एकता ज़िंदाबाद!
मज़दूर किसान एकता ज़िंदाबाद!
इंक़लाब ज़िंदाबाद!

http://hindi.cgpi.org/22065

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा

पृष्ठ 1 का शेष

बीते 75 वर्षों में इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में सरमायदारों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिन्दोस्तानी राज्य का इस्तेमाल करके, बड़े सुनियोजित तरीक़े से समाज के सभी तबकों के बीच में सांप्रदायिक ज़हर को फैलाया है। संविधान और देश के क़ानून मानवीय पहचान के बजाय, सांप्रदायिक पहचान को अहमियत देते हैं और जारी रखते हैं। सभी लोगों के साथ हिन्दोस्तानी नागरिक बतौर, समान बर्ताव नहीं किया जाता है। बल्कि "बहुसंख्यक समुदाय" या "अल्पसंख्यक समुदाय" का सदस्य होने के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, अलग–अलग लोगों के साथ अलग–अलग प्रकार का बर्ताव किया जाता है। देश के क़ानून और नीतियां दबे–कुचले लोगों को कुछ–थोड़ी राहत दिलाने के नाम पर, जातिवादी पहचान को भी बरक़रार रखती हैं।

बीते 75 वर्षों में इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में सरमायदारों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिन्दोस्तानी राज्य का इस्तेमाल करके, बड़े सुनियोजित तरीके से समाज के सभी तबकों के बीच में सांप्रदायिक ज़हर को फैलाया है। संविधान और देश के क़ानून मानवीय पहचान के बजाय, सांप्रदायिक पहचान को अहमियत देते हैं और जारी रखते हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य, जिसमें संसदीय राजनीतिक पार्टियां, प्रशासन तंत्र और सुरक्षा बल, सभी शामिल हैं, वह नियमित तौर पर अलग–अलग लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा का प्रयोग करता रहा है। हर ऐसे हिंसा–प्रयोग के दौर के बाद, हुक्मरान वर्ग का प्रचार–तंत्र लोगों को हिंसा के लिए दोषी बताता है। इस तरह हुक्मरान वर्ग ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारे देश के मज़दूर और किसान एकजुट होकर अपने सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़ संघर्ष न कर पाएं।

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा का शिकार न सिर्फ वे लोग होते हैं जिन्हें निशाना बनाया जाता है। बल्कि इस हिंसा का शिकार संपूर्ण मज़दूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोग हैं। शोषकों और दमनकारियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले लोगों की एकता भी इस हिंसा का शिकार है।

हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग ने अपनी भरोसेमंद पार्टियों के ज़रिए, अपनी खुफ़िया एजेंसियों के ज़रिए और राज्य के सुरक्षा बलों के ज़रिए, सांप्रदायिक हिंसा को आयोजित करने के तरीक़ों में बहुत कुशलता हासिल कर ली है। बहुत सोचे–समझे तरीके से भड़काऊ नारे दिए जाते हैं, भड़काऊ हरक़तें की जाती हैं, जैसे कि मस्जिद के अंदर सूअर का मांस फेंक दिया जाता है, मंदिरों के अंदर गाय का मांस फेंक दिया जाता है या धार्मिक ग्रंथों

शेष अगले पृष्ठ पर

हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच 2+2 वार्ता

अमरीकी साम्राज्यवाद ने हिन्दोस्तान पर अपने भू–राजनीतिक उद्देश्यों के साथ क़दम से क़दम मिलाने के लिए दबाव बढ़ाया

हिन्दोस्तान और अमरीका के बीच "2+2 वार्ता" का चौथा दौर 10 से 15 अप्रैल के बीच हुआ। 2+2 वार्ता में हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की अमरीका के विदेश मंत्री (जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है) तथा रक्षा सचिव की एक साथ बैठकें शामिल हैं। इनका मक़सद है कि दोनों राज्यों की विदेश और सैन्य नीतियों में नज़दीकी से समन्वय हो। अभी तक हिन्दोस्तान की केवल अमरीका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ताएं हुई हैं।

अमरीका के साथ हुई इस 2+2 बैठक का संदर्भ, इस तरह की पहले हुई वार्ताओं से अलग था। यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करके, अमरीकी साम्राज्यवाद, रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर करने और उसको अलग–थलग करने की हर तरह की कोशिश कर रहा है। अभी तक हिन्दोस्तानी राज्य ने यूक्रेन की स्थिति पर अपनी नीति को अमरीका और उसके सहयोगियों के साथ पंक्तिबद्ध नहीं किया है।

शीत युद्ध की अवधि के दौरान, सत्तारूढ़ हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदारों ने, दो महाशक्तियों, अमरीका और सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके अपनी शक्ति का विस्तार करने और दोनों से जो भी हासिल किया जा सकता था उसे प्राप्त करने की कोशिश की। सोवियत संघ के पतन और दुनिया के दो–ध्रुवीय विभाजन के खात्मे के बाद, हिन्दोस्तानी राज्य ने अमरीका के साथ और क़रीबी संबंध बनाए हैं। साथ ही, हिन्दोस्तान ने अभी भी रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दोस्तान के सैन्य उपकरणों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रूस से आयात किया जाता है।

यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पैदा होने के बाद, हिन्दोस्तान ने अभी तक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के ख़िलाफ़ मतदान नहीं किया है। हिन्दोस्तान ने रूसी तेल की अपनी ख़रीद को भी बढ़ा दिया है और रूस के साथ लेनदेन पर अमरीका के नेतृत्व में लगाये गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए रुपया–रूबल की भुगतान व्यवस्था विकसित करने की कोशिश कर रहा है।

इन परिस्थितियों में, यह स्वभाविक उम्मीद की जानी चाहिए कि अमरीका के साथ हाल में हुई 2+2 वार्ता में, अमरीकी साम्राज्यवाद, हिन्दोस्तान पर अपने रुख़ को बदलने और कई सैन्य उपकरणों और अन्य रियायतों के बदले में, हिन्दोस्तान को अमरीका अपने उद्देश्यों के अनुरूप चलने के लिए दबाव बनाने का हर संभव प्रयास करेगा।

पिछले कुछ दशकों में, अमरीका के साथ और क़रीबी संबंध बनाने की, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग की खुदगर्ज़ नीति ने हिन्दोस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय, हिन्दोस्तान को और कमज़ोर बनाया है। एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति जो हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय हित में है, उसको बनाए रखने में सक्षम होने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ रणनीतिक संबंधों को तोड़ना अति–आवश्यक है।

2+2 की बैठक के दौरान क्या हुआ?

एक आश्चर्यजनक क़दम देखने में आया कि हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, उनके अमरीकी समकक्षों एंथनी ब्लिंकेन और लॉयड ऑस्टिन के साथ वार्ता की पूर्वसंध्या पर, अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हिन्दोस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अचानक एक ऑनलाइन शिखर वार्ता की।

यह शिखर वार्ता स्पष्ट रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ पंक्तिबद्ध करने के लिए, उच्चतम स्तर पर, हिन्दोस्तान पर दबाव बनाने का एक प्रयास था।

हालांकि शिखर वार्ता में वास्तव में क्या हुआ, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिन्दोस्तानी राज्य ने अभी तक रूस–यूक्रेन पर अपना रुख़ नहीं बदला है।

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2+2 वार्ता से की गयी उम्मीद के अनुसार, कुछ प्रमुख घोषणायें नहीं हुईं। इसमें, हिन्दोस्तान की तीन सशस्त्र सेवाओं के लिए, अमरीका से 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोनों की ख़रीद के लिए एक समझौता शामिल था। इसके अलावा, यह भी उम्मीद की जा रही थी कि अमरीका काऊंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन्स एक्ट, यानी कि प्रतिबंधों के माध्यम से अमरीका के विरोधियों पर पाबंदियों के प्रावधानों को हिन्दोस्तान के ख़िलाफ़ न लगाने के अपने इरादे की घोषणा करेगा। इससे 2018 में रूस से, एस–400 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स की ख़रीद के लिए हिन्दोस्तान को अमरीका द्वारा दंडित करने से रोका जा सकता था। ऐसी किसी छूट की घोषणा नहीं की गई।

हालांकि, इन बैठकों में दोनों देशों के बीच, कुछ अन्य प्रकार के सैन्य–सहयोग पर चर्चा की गई। इसमें अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरुकता समझौते पर एक घोषणा, विस्तारित संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना और एक साइबरस्पेस वार्ता शामिल हैं। एक अभूतपूर्व क़दम के रूप में, दोनों पक्षों ने अमरीकी नौसैनिक जहाजों की यात्रा के दौरान मरम्मत के लिए अमरीका द्वारा हिन्दोस्तानी शिपयार्ड का इस्तेमाल करने के लिए समझौते पर चर्चा की।

गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने उन्नत प्रणालियों के सह–उत्पादन, सह–विकास और सहकारी परीक्षण पर चर्चा की। अमरीका से सैन्य उपकरण ख़रीदने के हिन्दोस्तान के लिए प्रमुख शर्तों में से एक है – 2009 में हस्ताक्षरित अंतिम उपयोग निगरानी समझौते के प्रावधान। यह हिन्दोस्तान को अमरीका से ख़रीदे गए सैन्य उपकरणों में अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनमें बदलाव करने से रोकता है। यह प्रावधान, हिन्दोस्तान को मूल–निर्माताओं के अलावा, किसी अन्य देश या पार्टी से स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने या ऐसे उपकरणों की सर्विसिंग कराने से भी रोकता है। रूस से ख़रीदे गए सैन्य उपकरणों को इस तरह के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

वर्तमान हालातों में, अमरीका रूस के सैन्य उद्योग को कमज़ोर करने के लिए बहुत उत्सुक है। हिन्दोस्तानी बाज़ार को खोना रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यही कारण है कि इस बैठक में, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अपने वादे के साथ, सैन्य उपकरणों के सह–उत्पादन की संभावनाओं का प्रलोभन दिखाकर, अमरीकी वार्ताकारों की कोशिश थी कि हिन्दोस्तान को रूसी सैन्य उपकरणों के सप्लायरों से दूर किया जाए।

विभिन्न समीक्षा लेखों में बताया गया है कि इस 2+2 वार्ता में अमरीका और हिन्दोस्तान, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर 'असहमत रहने के लिए सहमत' हुए हैं। यह एक ग़लत आकलन है। अमरीकी साम्राज्यवाद अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा और रूस को कमज़ोर करके उसे अलग–थलग करना, इनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक बड़े देश और अमरीका के कथित 'रणनीतिक साझेदार' के रूप में, रूस के प्रति अपनी नीति को अमरीका और उसके सहयोगियों के साथ पंक्तिबद्ध करने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य की अनिच्छा, अमरीकी साम्राज्यवाद को मंजूर नहीं है। वे चुपचाप बैठकर इस असहमति को सहन नहीं करेंगे, बल्कि हिन्दोस्तान के ऊपर, वे अपने शस्त्रागार के सभी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक, हथियारों से हमला करके यह दबाव बनाये रखेंगे। पिछले कुछ दशकों में, अमरीका के साथ और क़रीबी संबंध बनाने की, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग की खुदगर्ज़ नीति ने हिन्दोस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय, हिन्दोस्तान को और कमज़ोर बनाया है। एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति जो हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय हित में है, उसको बनाए रखने में सक्षम होने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ रणनीतिक संबंधों को तोड़ना अति–आवश्यक है।

http://hindi.cgpi.org/22060

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा

पृष्ठ 2 का शेष

को नष्ट किया जाता है। राज्य के एजेंट लोगों को भड़काने के लिए तरह–तरह की झूठी अफ़वाहें फैलाते हैं, जैसे कि 1984 में उन्होंने इस प्रकार की अफ़वाह फैलाई थी कि लोगों के पीने के पानी के कुंओं में ज़हर मिला दिया गया है।

हिंसक हमलों को अंजाम देने वाले गुंडों को राज्य की पूरी सुरक्षा मिलती है। ये गुंडे धार्मिक वेश धारण कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हमला कर रहे हैं।

जब से हिन्दोस्तान आज़ाद हुआ है, उस समय से आज तक, हमने बार–बार राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक क़त्लेआम के अनेक कांड देखे हैं, जिनमें 1984 और 2002 के जनसंहार भी शामिल हैं। इस दौरान, कई अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संभाला है, परंतु जनसंहार को आयोजित करने वालों को आज तक कोई सज़ा नहीं दी गई है। इससे साबित होता है कि ये जनसंहार हुक्मरान वर्ग के आदेश के अनुसार किये गए थे। ये जनसंहार "दंगे–फ़साद" नहीं थे, बल्कि लोगों के ख़िलाफ़ राज्य द्वारा आयोजित अपराध थे। सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करना हुक्मरान सरमायदार वर्ग का एक पसंदीदा तरीक़ा है, जिसके ज़रिए वह मज़दूरों, किसानों और सभी दबे–कुचले लोगों की एकता को चकनाचूर करता है।

हुक्मरान वर्ग को इस समय, उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिए भूमंडलीकरण की हुकूमत को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। ऐसा करके ही हम उस नए समाज का निर्माण कर पाएंगे, जो हर प्रकार के शोषण और दमन से मुक्त होगा। ऐसा करके ही हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि सभी के ज़मीर के अधिकार की गारंटी दी जाएगी और अपने विचारों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या किसी पर हमला नहीं किया जाएगा।

http://hindi.cgpi.org/22051

Internet Edition
Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 May, 2022 Date of publish - 1 May, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों का संघर्ष जारी

केंद्र सरकार द्वारा तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को वापस लेने के बाद, किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर चलाया जा रहा विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। आंदोलन के स्थगित होने के चार महीने बाद पंजाब और हरियाणा तथा अन्य राज्यों में किसान संगठन संघर्ष को जारी रखने के लिए सक्रिय रूप से लोगों को लामबंध कर रहे हैं।

किसान संगठन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि किसानों की शेष सभी मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2021 को लिखित में दिया था, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया था, वह आश्वासन महज दिखावा था। विभिन्न फ़सलों के लिए एम.एस.पी. निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने के लिये सरकार द्वारा आज तक कोई क़दम नहीं उठाया गया है। वादे के मुताबिक आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ पुलिस मामले वापस लिये जाने थे जो अभी तक नहीं लिए गए हैं। कई किसान अभी भी हिरासत में हैं। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को वादा किया गया मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला है। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की हत्या के मुख्य दोषी अजय मिश्रा टेनी को सज़ा नहीं मिली है। किसान संगठनों ने महसूस किया है कि उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों के साथ–साथ पूरे देश में एक साथ आने और आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।

पंजाब में किसानों द्वारा हाल ही में किये गये कुछ विरोध कार्यक्रमों की रिपोर्टों को हम नीचे दे रहे हैं :

29 मार्च को अमृतसर के भगतनवाला अनाज मंडी में किसान संगठनों ने एक विशाल रैली की। इस रैली में अमृतसर और गुरदासपुर जिलों से किसान शामिल हुये, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब राज्य के अधिकारों की बहाली की मांग की। उन्होंने ट्रेड यूनियनों और

अमृतसर की भगतनवाला अनाज मंडी में किसान संगठनों की विशाल रैली, 29 मार्च

मज़दूर संगठनों की दो दिवसीय सर्व हिन्द हड़ताल का समर्थन किया।

इस रैली का आयोजन किसान–मज़दूर संघर्ष समिति, पंजाब की ओर से किया गया था। वक्ताओं ने दिसंबर 2021 में आंदोलन की वापसी के समय किए गए अपने वादों पर मुकर जाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने में विफलता के लिये और गेहूं की फ़सल की ख़रीद में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के साथ–साथ चालू सीजन के दौरान पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाने के लिए सरकार की निंदा भी की।

29 मार्च को बी.के.यू. एकता (उग्राहां) के बैनर तले पंजाब के मुक्तसर जिले में लंबी उप–तहसील के बाहर सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे कपास की अपनी फ़सल को गुलाबी बॉलवर्म से हुई क्षति के लिए लंबे समय से मुआवज़ा न मिलने का विरोध कर रहे थे। आंदोलन के दौरान, उन्होंने कई घंटों तक एक उप–तहसील कार्यालय के अंदर सरकारी अधिकारियों का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान घायल हो गए। पुलिस ने कुछ आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी भी दर्ज़ की।

बीकेयू एकता (उग्राहां) और अन्य किसान यूनियनों ने 7 अप्रैल को बठिंडा से शुरू होकर गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर नियमित बैठकों और घर–घर जाकर प्रचार का अभियान चलाया। यह सर्व हिन्द विरोध, 'एम.एस.पी. गारंटी सप्ताह' (11 से 17 अप्रैल) मनाने के लिए एस.के.एम. के आह्वान का एक हिस्सा था। लुधियाना में एक राज्य–स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें 12 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में किसानों ने 29 मार्च को पंजाब बॉर्डर एरिया किसान यूनियन के बैनर तले तरन तारन में स्थानीय जिला प्रशासन परिसर (डी.ए.सी.) के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, हिन्दोस्तानी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है उन्हें मुआवज़े के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना है जो पिछले 4 वर्षों से लंबित है। उन्होंने इस मुआवज़े के शीघ्र भुगतान के साथ–साथ सीमा पर गश्त के लिए बी.एस.एफ. द्वारा ली गई ज़मीन के मुआवज़े की मांग की। उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा।

25 मार्च को एस.के.एम. के बैनर तले सैकड़ों किसान मोहाली में गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब के सामने जमा हुए। उन्होंने तीन कृषि क़ानूनों को रद्द करने के समय केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी वादे पूरे होने तक संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। उनकी अन्य मांगों में संसद द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम–2021 को वापस लेना शामिल है, जिसका उद्देश्य देश की नदियों पर बने बांधों के पानी और बिजली को कॉरपोरेट घरानों को सौंपना तथा भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के स्थायी प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के निर्णय को रद्द करना।

इससे पहले इसी दिन, किसानों ने चंडीगढ़ में राजभवन तक एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें वाई.पी.एस. चौक पर रोक दिया। इसके बाद वे मोहाली–चंडीगढ़ सीमा पर स्थित गीता मंदिर के पास धरने पर बैठ गए। बाद में, 35 सदस्यीय किसान प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल के माध्यम से हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों का चार्टर हरियाणा के राज्यपाल को भी सौंपा।

रोहतक में 22 मार्च को कई किसान संगठनों ने जाट धर्मशाला से करनाल मिनी सचिवालय तक जुलूस निकाला और धरना दिया। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।

कीर्ति किसान यूनियन (के.के.यू.) ने 21 अप्रैल को घोषणा की कि वह किसानों से कर्ज़ की वसूली के लिए सहकारी बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे कठोर उपायों का विरोध करने के लिए पंजाब सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेगी। यूनियन ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों को किसानों से कर्ज की वसूली के लिए कड़े क़दम उठाने के निर्देश दिए हैं। यूनियन ने घोषणा की कि वह किसानों की गिरफ़्तारी और उनकी संपत्तियों की कुर्की का कड़ा विरोध करेगी। यूनियन ने बताया कि इस साल गेहूं की पैदावार में काफी कमी आई है। किसान क़र्ज़ की किश्त नहीं चुका सकते। उन्होंने मांग की है कि छोटे किसानों का पूरा क़र्ज़ तत्काल माफ़ किया जाए।

किसानों का लगातार हो रहा आंदोलन दिखाता है कि किसान केंद्र सरकार के झूठे वादों को मानने के विचार में नहीं हैं।

http://hindi.cgpi.org/22054

पाठकों की प्रतिक्रिया

साम्राज्यवादी दख़ल की जितनी निंदा की जाए थोड़ी है!

संपादक महोदय,

आपके अख़बार के पिछले अंक में पाकिस्तान के संदर्भ में साम्राज्यवादी दख़ल का जो मुद्दा उठाया है वह बेहद महत्वपूर्ण है। जिसके लिये मैं धन्यवाद करती हूं।

आज विश्व स्तर पर जो अलग–अलग देशों में साधारण व ग़रीब जनता शोषण, तंगहाली व आतंक का जीवन जीने को मजबूर है उसके लिए उनके देश में शासकों के साथ–साथ साम्राज्यवादी नीतियों को मानने की सोच व व्यवहार दोषी है। साम्राज्यवादी दख़ल सिर्फ सरकारें ही नहीं हटाता बल्कि वह वहां की आंतरिक ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। इस दख़ल के कारण दो देशों में तनाव के साथ–साथ वहां के आस–पास के अन्य देशों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि यूक्रेन–रूस के बीच अमरीकी व यूरोपीय देशों की दख़ल के कारण तनाव पनपा और अब गंभीर रूप ले चुका है। रूस और अमरीका व उनके सहयोगियों द्वारा अनेकों पाबंदियां लगाना फिर रूस द्वारा भी अनेकों पाबंदी लगाना। इन सबसे अनाज, तेल, खाद्य आदि अनेक ज़रूरी चीजों की भारी कमी व दाम बढ़ने की समस्या विश्व का बड़ा भाग झेल रहा है।

यूक्रेन में शांति क़ायम करने के लिये तथा वहां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूक्रेनी जनता को अपनी सरकार के साथ–साथ अमरीकी व अन्य साम्राज्यवादियों की दख़ल बंद करने का भी ज़ोरदार संघर्ष करना होगा।

हमें भी अपने देश में इस समस्या के प्रति सचेत रहना होगा। कृषि का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सुरक्षा संबंधी क्षेत्र हो, सभी में साम्राज्यवादी नीतियों के ख़िलाफ़ अधिकांश जनता को लामबंध किए बिना हम आतंरिक समस्याओं के ख़िलाफ़ संघर्ष को ठीक से विकसित व सफल नहीं कर पायेंगे।

आइए, अमरीकी व अन्य साम्राज्यवादी दख़ल के विरोध में संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

निर्मल, दिल्ली